प्रेस-विज्ञाप्ति दिनाँक : 21.10.2021

विषय : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कानपुर के उद्योगों में होने वाली आधारभूत समस्याओं के साथ समाधान पर गहन मंथन

मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने श्री ए.के. शर्मा के साथ दिनांक 10.08.2021 को हुई बैठक में कानपुर के उद्योगों में होने वाली कठिनाइयों से संबंधित टेबुलर फॉर्म में विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर हल की जाने वाली समस्याओं को लिखकर के दिया था। उन सभी समस्याओं को श्री ए.के. शर्मा जी ने अपने स्तर से कई मंत्रालयों व विभागों को प्रेषित किया था। इसी अनुक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, के लॉजिस्टिक डिवीज़न द्वारा एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग दोपहर 12 बजे बुलाई गयी थी। इस मीटिंग में वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, श्री अरविन्द कुमार – Additional Chief Secretary, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री एन. निवास- निदेशक - डी.एफ.सी.सी.आई.एल. (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया), श्री उपमन्यु बसु, JS (LH), AQCS (Animal Quarantine and Certification Services), श्री सैंथिल नाथन - निदेशक, SEZ, श्री विशाख जी.-आई.ए.एस., जिलाधिकारी, कानपुर नगर, तथा मर्चेंट्स चेम्बर की ओर से अध्यक्ष-श्री अतुल कनोडिया, श्री आरके जालान, श्री आर.के. लोहिया, श्री मनीष कटारिया, श्री सुशील शर्मा, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री अविरल जैन तथा सचिव- महेंद्र नाथ मोदी आदि उपस्थित थे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से 3 समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ :

1. **पूर्ण विकसित लॉजिस्टिक पार्क** की आवश्यकता - ताकि उत्पादन की लागत तथा समय को बचाया जा सके। वर्तमान में कानपुर में दो लॉजिस्टिक पार्क है: पहला कॉन्कर्ड, फजल गंज में तथा दूसरा निजी क्षेत्र में कानपुर लॉजिस्टिक पार्क। मर्चेंट्स चैम्बर के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से यह सुझाव दिया कि एक पूर्ण रूप से विकसित ROW-ROW Model पर आधारित लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाए ताकि उत्पादन लागत में कमी हो तथा समय की बचत भी हो सके। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव RITES के प्रस्ताव में है। इस पर सरकार गंभीरता के साथ विचारकर इस पार्क के क्रियान्वन में शीघ्रता से आगे बढ़ेगी।

2. **कच्चा चमड़ा** कानपुर में लेदर उद्योग बहुतायत में है तथा कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या हमेशा बनी रहती है। कच्चे माल को विदेश से आयात करना पड़ता है। वर्तमान में मुंबई, दिल्ली, जालंधर में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) है। कानपुर में यह सुविधा नहीं है। दिल्ली व जालंधर में मिलने वाली सुविधा कानपुर को उपलब्ध कराये जाने पर मर्चेंट्स चैम्बर ने अपनी मांग रखी। इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा नई लैब को बनाने की है। विचार-विमर्श के पश्चात् UPSIDA को ट्रांस गंगा में नयी लैब को बनाने के लिए रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। फौरी तौर पर राहत लेने के लिए इटावा स्थित लैब से सुविधा देने की बात पर सहमति बनी है। इसके लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा चुका है तथा इसकी प्रति श्री उपमन्यु बासु, जे.एस., AQCS (Animal Quarantine and Certification Services) को आज भेज दी जाएगी। इस दिशा में शीघ्र कार्य होने की सहमति बन गयी है।
3. **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** कानपुर शहर व उसके आस-पास वर्तमान में विशेष आर्थिक जोन नहीं है। SEZ की स्थापना के लिए DM, कानपुर को यह निर्देश दिए गए है कि वे UPSIDA, NHAI व मर्चेंट्स चेम्बर के साथ मिलकर बैठक करें तथा जो प्रस्तावित आउटर रिंग रोड है उसी क्षेत्र में जमीन

देखकर प्रस्ताव बनाये। सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति बनी कि कानपुर क्षेत्र में SEZ बनाया जाना चाहिए।